(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह डाक-टिकट मद्रास के मुख्य मंत्री की प्रार्थना पर जारी किया गया था। इसमें सम्मेलन के 'एम्ब्लेम' का ठीक वैसा ही चित्र दिया गया है जैसा कि उन्होंने भेजा था।

LOW PRICE OF FOODGRAINS IN PUNJAB AND HARYANA

*61. SHRI N. K. P. SALVE:
SHRI YAJNA DATT SHARMA:
SHRI Y. S. KUSHWAH:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the stocks of foodgrains particularly of wheat far exceeded the demand in the markets in the States of Haryana and Punjab and are selling at extra-ordinarily low prices;

(b) whether the same commodity is selling at very high prices in the neighbouring States of Delhi and U.P.; and

(c) if so, whether Government propose to readjust the Food Zones in the light of these circumstances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) Punjab and Haryana being surplus States, the availability of foodgrains generally exceeds the local demand. The prices of foodgrains including wheat have fallen since October, 1967 in the States of Haryana and Punjab. The falling trend in pices is because of a good *kharif* crop in the case of *kharif* cereals and expectation of a good *rabi* crop in the case of the State Government, Co-operatives and the F.C.I. make purchases of foodgrains at the procurement prices to ensure that the prices do not fall below the level of the procurement prices.

(b) The prices of wheat in Delhi and U.P. are somewhat higher than in Haryana and Punjab. There is always some difference in prices between the surplus and deficit States.

(c) The matter of zonal restrictions will be considered as usual in the next meeting of the Chief Ministers called to consider *Rabi* Policy.

आयातित गेहूं तथा माइलो के मूल्यों में वृद्धि

*71. **श्री मधु लिमये :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के पश्चात् सरकार ने अमरीका से आयात किये गये गेहूं और माइलो के विक्रय मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रति किलो बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) किन-किन राज्यों ने इस वृद्धि के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(घ) गेहूं के मूल्य में उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय भंडार से सप्लाई किए जाने वाले आयातित गेहूं तथा माइलो के निर्गम मूल्य पहली जनवरी, 1968 से बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) आयातित गेहूं तथा माइलो के निर्गम में क्रमश: 12 पैसे और 8 पैसे प्रति

किलो की वृद्धि हुई है। केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में आयातित गेहूं के निर्गम मूल्य में 11 पैसे प्रति किलो की वृद्धि हुई है।

(ग) बिहार सरकार ने आयातित गेहूं तथा माइलो के निर्गम मूल्यों में की गई वृद्धि के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है।

(घ) हालांकि जनवरी, 1968 के शुरू में खाद्यान्नों के बाजार-मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी, लेकिन जनवरी, 1968 के उत्तरार्ध में गेहूं व मोटे अनाजों के मूल्यों में गिरावट का रुख आया है।

गुप्त मतदान द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता

*72. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कार्मिक संघों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता प्रदान करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिद्धांत के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

STRIKE THREAT BY F.C.I. EMPLOYEES

*74. SHRI UMANATH:
SHRI A. K. GOPALAN:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:
SHRI MOHAMMAD ISMAIL:

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the Food Corporation of India have decided to observe pay strike and also to go on a token strike;

(b) if so, what are their demands; and

(c) the steps taken by the Government to settle the dispute?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) On 31st January, 1968, the transferees of the erstwhile Northern Region of the Department of Food working at the head office of the Corporation at Delhi as also in Punjab, Jaipur, U.P. regions of Food Corporation of India held peaceful demonstrations at 5 P.M. and also deferred by one day the acceptance of their salaries for the month of January, 1968.

(b) A statement showing their demands is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(i) Stoppage of further direct recruitment and creation of equivalent number of posts, in various cadres in comparison with the number of staff already recruited directly and filling up the same by due promotions to Food Transferees.

(ii) Sending back of all the deputationists working in the Food Corporation to their parent Departments and total stoppage of bringing in any more deputationists.

(iii) Promotion of all qualified Class IV staff (within Matrics and upwards) to Class III cadre and stoppage of direct recruitment of Assistant Grade III till all qualified Class IV staff is promoted.

(iv) Sanction of *Ex-gratia* grant to